पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2016 का आपराधिक विविध/प्रकीर्ण सं. 37923

पीएस मामला सं.-74 वर्ष-2013 थाना-पूर्णिया शिकायत मामला जिला-पूर्णिया से उत्पन्न

=====

राम पुकार राय, सरयुग राय का पुत्र, गाँव-फुलवारिया, पी. एस.-कोरहा, जिला-कटिहार
का निवासी।

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेम चंद सिंह, मोहल्ला-शयोपुरी, पी.एस- के.हाट, जिला-पूर्णिया के निवासी।

..... विपरीत पक्ष/पक्षों

=====

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : - श्री बखशी एस. आर. पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार सिंह,
राज्य के अधिवक्ता :- श्री सुनील कुमार पांडे, एपीपी
ओ. पी. नंबर 2 के लिए :- कोई नहीं

=====

अधिनियम/धारा/नियम:

- भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 464, 467, 468, 471 और 120 बी

संदर्भित मामले:

- अमित सिन्हा बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 6330
- हरिहर साह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन पैट 9582
- सुशील सूरी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, [एआईआर 2011 एससी 1713]
- मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, [(2009) 8 एससीसी 751]
- रणधीर सिंह बनाम यूपी राज्य, [(2021) 14 एससीसी 626]
- यूरेका बिल्डर्स बनाम गुलाबचंद, (2018) 8 एससीसी 67
- विनायक अरोलकर बनाम गोवा राज्य एवं अन्य। (सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 2024 का 39)

याचिका- उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जिसके तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अभियुक्तों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, के विरुद्ध संज्ञान लिया और कार्यालय को उनके विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया।

निर्णय-

किसी अपराध का संज्ञान लेने और किसी अभियुक्त को समन जारी करने के लिए आवश्यक है कि शिकायत में किए गए आरोप और धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच के दौरान शिकायतकर्ता और उसके गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर एक प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित होता हो। हालांकि, ऐसे आरोप या बयान पूर्णतः निराधार और असंभव प्रतीत नहीं होने चाहिए। साथ ही, शिकायत और धारा 200 आ.दं.सं. के तहत जांच के दौरान दिए गए बयानों को संपूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन इस स्तर पर उनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। - यदि प्रस्तुत तथ्य मात्र एक दीवानी विवाद को दर्शाते हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्यायहित को सुनिश्चित करने के लिए शिकायत या संज्ञान/समन आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। (पैरा 12)

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करने के लिए शिकायतकर्ता से कोई प्रतिनिधित्व किया हो। लेकिन इस मामले में, शिकायतकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया है कि किसी भी अभियुक्त ने उसे कोई संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए कोई प्रतिनिधित्व किया। अतः किसी प्रतिनिधित्व के अभाव में, शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। (पैरा 27)

शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों को कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की और न ही उसने बिक्री विलेख निष्पादित किया। अतः यदि उसके पास भूमि का कोई स्वामित्व था, तो वह सुरक्षित है, क्योंकि यदि विलेख किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है जिसे भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, तो उससे स्वामित्व स्थानांतरित नहीं हो सकता। (पैरा 28)

भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तत्व भी पूरे नहीं होते। याचिकाकर्ता और सह-आरोपियों के बीच किसी भी अवैध कृत्य को करने के लिए किसी प्रकार के समझौते का आरोप नहीं लगाया गया है। (पैरा 31)

प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अधिकतम यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह पक्षकारों के बीच विशुद्ध रूप से एक दीवानी विवाद है, जिसका समाधान उपयुक्त दीवानी वाद दायर करके दीवानी न्यायालय में किया जाना चाहिए। (पैरा 32)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैरा 33)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

तिथि - 10-01-2025

वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा धारा 482 आ.दं.सं के तहत, 2013 के शिकायत मामला संख्या 74 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित दिनांकित 04.01.2016 के आदेश पर आक्षेप करते हुए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान दंडाधिकारी ने याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड

संहिता की धारा 420,467,468,471 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है और कार्यालय को उनके खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया है।

अभियोजन का मामला

2. विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा दायर 2013 की आपराधिक शिकायत संख्या 74 से सामने आने वाले/उत्पन्न आरोप का योग और सार यह है कि 29 दशमलव माप वाली जमीन खाता संख्या 299, खेसरा संख्या 1198 वाली भूमि का अंश है, शिकायतकर्ता/विरोधी पक्ष संख्या 2 की है। यह आगे आरोप लगाया गया है कि उसी भूमि के संबंध में, सह-अभियुक्त जगदीश प्रसाद पोद्दार ने सह-अभियुक्त व्यक्ति यानी अरुण उरांव के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया। मिथीलेश सिंह और नरेश कुमार सिंह इस पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन के गवाह थे। आगे यह आरोप लगाया गया है कि उस भूमि का कुछ हिस्सा पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अरुण उरांव द्वारा सह-अभियुक्त राम पुकार राय के पक्ष में बेचा गया था, जो इसमें याचिकाकर्ता हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता/राम पुकार राय ने सह-आरोपी राज कुमार चौधरी को जमीन बेच दी। इसलिए, याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों ने जालसाजी की है और शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है। विलेख की बिक्री और पावर ऑफ अटॉर्नी पूर्णिया निबंधन कार्यालय में पंजीकृत किए गए हैं।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. शिकायत दर्ज करने के बाद, शिकायतकर्ता और एक जांच गवाह, अनंत कुमार सिंह, जो शिकायतकर्ता/संतोष कुमार सिंह के भाई हैं, से धारा 200 आ.दं.सं. के तहत पूछताछ की गई। जांच के दौरान, यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि उनकी है, क्योंकि यह उनके पिता द्वारा खरीदी गई थी। हालाँकि, उस भूमि के संबंध में, एक जगदीश प्रसाद पोद्दार ने अरुण उरांव के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन किया

है और उसे पूर्णिया निबंधन कार्यालय में पंजीकृत किया गया था और उसके बाद, अरुण उरांव ने एक रवींद्र राय के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित किया है।

4. शिकायत और जांच के दौरान गवाहों के बयानों के आधार पर, याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए और समन जारी करते हुए विवादित आदेश पारित किया गया था। अतः याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका लाया गया है।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के लिए विद्वान एपीपी को सुना। हालाँकि, अवसर के बावजूद विरोधी पक्ष सं. 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुति

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने उचित राशि के भुगतान के बाद प्रश्नगत भूमि अरुण उरांव से, जो सह-अभियुक्त जगदीश प्रसाद पोद्दार से भूमि के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी है, खरीदी है। और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध करने का कोई सवाल ही नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि कथित तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए भी, केवल विवाद जो उत्पन्न होता है वह प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के बारे में है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जमीन उसकी है क्योंकि उसे यह जमीन अपने पिता से विरासत में मिली थी और जमीन अरुण उरांव ने रवींद्र राय को बेच दी है। इसलिए, मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों से कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

7. वह आगे प्रस्तुत करता है कि भले ही यह माना जाता है कि भूमि विरोधी पक्ष संख्या 2 (शिकायतकर्ता), अर्थात् संतोष कुमार की है और बिक्री-विलेख किसी और द्वारा निष्पादित किया गया है, खरीदार को कोई अधिकार/हक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह कानून का तय सिद्धांत है कि कोई भी अपने से बेहतर अधिकार हस्तांतरित नहीं कर

सकता है। इसलिए, शिकायतकर्ता/विरोधी पक्ष संख्या 2/संतोष कुमार को कोई नुकसान नहीं हुआ है और धोखाधड़ी का अपराध करने का कोई सवाल ही नहीं है।

8. वह यह भी प्रस्तुत करता है कि जालसाजी का कथित अपराध भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि रिकॉर्ड पर सामग्री के अनुसार, किसी भी दस्तावेज पर जाली होने का आरोप नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी और बिक्री विलेख दोनों ही वास्तविक हैं।

9. इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, कथित तथ्य और परिस्थितियां, अधिक से अधिक, विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति का विवाद हैं और विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द और अपास्त किया जा सकता है।

10. वह इस न्यायालय के निम्नलिखित दो निर्णयों का भी उल्लेख करता है और उन पर निर्भर करता है:

(i) अमित सिन्हा बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 6330, ए.आई.आर ऑनलाइन 2024 पैट 468;

(ii) हरिहर साह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 9582, ए.आई.आर ऑनलाइन 2023 पैट 929।

राज्य की ओर से प्रस्तुति

11. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान एपीपी विवादित आदेश का बचाव करते हुए कहता है कि इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज की जा सकती है।

धारा 482 का दायरा/सीमा और व्यापकता आ.दं.सं.

12. इससे पहले कि मैं पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूँ, आ.दं.सं. की धारा 482 के दायरे/सामा और व्यापकता को देखना उचित होगा। यहाँ अमित सिन्हा मामला (सुप्रा) और हरिहर साह मामला (सुप्रा), का उल्लेख करना

लाभदायक होगा, जिसमें इस न्यायालय ने सुसंगत वैधानिक प्रावधानों और बाध्यकारी न्यायिक पूर्वनिर्णयों का उल्लेख करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी अपराध का संज्ञान लेने और शिकायत मामले में किसी भी आरोपी को समन जारी करने के लिए, शिकायत में लगाए गए आरोप और धारा 202 आ.दं.सं. के तहत जांच के दौरान शिकायतकर्ता और उसके गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर *प्रथम दृष्टया* अपराध किया जाना चाहिए। हालाँकि, ऐसा आरोप या बयान स्पष्ट रूप से बेतुका और विवेकपूर्ण/प्रज्ञावान दिमाग के लिए स्वाभाविक रूप से असंभव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, शिकायत में और जांच के दौरान लगाए गए आरोप/बयान की धारा 200 आ.दं.सं. के तहत समग्र रूप से जांच की जानी चाहिए, लेकिन इस स्तर पर ऐसे बयानों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है या नहीं। इसके अलावा, यदि तथ्यों का दिया गया समूह केवल एक दीवानी विवाद बनाता है, तो अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए शिकायत या संज्ञान/समन आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

13. अब, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप या गवाहों के बयान, जो उनके समर्थन में उनके अंकित मूल्य पर दर्ज किए गए हैं, अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला बनाते हैं।

14. शिकायत में आरोप और धारा 200 आ.दं.सं., के तहत जांच के दौरान शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयानों के अनुसार। विद्वान दंडाधिकारी ने दिनांक 04.01.2016 के विवादित आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 467,468,471,420 और 120 बी के दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है।

15. भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी के लिए सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 468 जाली दस्तावेज या धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उपयोग करने के इरादे से जालसाजी करने के लिए सजा का प्रावधान करती है। अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है। धारा 471 में धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को वास्तविक के रूप में उपयोग करने के लिए सजा का प्रावधान है जिसे वह जानता है या जिसके पास इसे जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मानने का कारण है।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने के लिए धोखा दिए गए व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित करना या मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी भी हिस्से को बनाने, बदलने, या नष्ट करने के लिए या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या सील किया गया है और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है। इस अपराध के लिए सात साल तक की सजा हो सकती है।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान करती है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति करने के लिए सहमत होते हैं, या करने का कारण बनते हैं (i) एक अवैध कार्य या (ii) एक ऐसा कार्य जो अवैध तरीकों से अवैध नहीं है, तो ऐसे समझौते को आपराधिक साजिश के रूप में नामित किया जाता है।

18. वर्तमान मामले पर आते हुए, मैंने पाया कि आरोप का योग और सार यह है कि शिकायतकर्ता की भूमि संपत्ति को सह-आरोपी अरुण उरांव द्वारा सह-आरोपी जगदीशप्रसाद पोद्दार . के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप बिक्री विलेख द्वारा अभियुक्त/याचिकाकर्ता को में बेचा गया है।

19. इस न्यायालय के विचार के लिए पहला सवाल यह उठता है कि क्या सह-अभियुक्त अरुण उरांव द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित बिक्री-विलेख को जाली दस्तावेज माना जा सकता है।

20. भारतीय दंड संहिता की धारा 463 में जालसाजी को परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित रूप में प्रदान करता है:

“463. कूटरचना— जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से, या किसी भी दावे या स्वामित्व का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए, या किसी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी की जा सकती है, कोई भी गलत दस्तावेज या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है, वह जालसाजी करता है।

21. जालसाजी की मूल सामग्री जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुशील सूरी बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, [ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1713] मामले में समझाया गया है , इस प्रकार है:

1) किसी झूठे/मिथ्या दस्तावेज या उसके हिस्से को बनाना और (2) ऐसा बनाना उस इरादे से होना चाहिए जो धारा में निर्दिष्ट है।, अर्थात् (क) (i) जनता, या (ii) किसी व्यक्ति को नुकसान या उल्लंघन करना; या (ख) किसी दावे या अधिकार/स्वामित्व का समर्थन करना; या (ग) किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए प्रेरित करना, या (घ) किसी व्यक्ति को एक व्यक्त या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना; या (ङ) धोखाधड़ी करना या धोखाधड़ी की जा सकती है ।

22. भारतीय दंड संहिता की धारा 464 झूठे दस्तावेज बनाने को परिभाषित करती है। यह इस प्रकार है:

“464. झूठा दस्तावेज बनाना-

एक व्यक्ति को झूठा/मिथ्या दस्तावेज या झूठा/मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा जाता है-पहले- जो बेईमानी से या छलपूर्वक -

(क) किसी दस्तावेज या दस्तावेज के हिस्से को बनाता है, हस्ताक्षर करता है, मुहर लगाता है या निष्पादित करता है;

(ख) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का हिस्सा बनाता है या प्रसारित करता है;

(ग) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को चिपकाता है;

(घ) किसी दस्तावेज के निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को दर्शाने वाला कोई भी निशान बनाता है,

यह विश्वास दिलाने के इरादे से कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज का हिस्सा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसी ऐसे व्यक्ति के प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे, मुहर लगाई गई थी, निष्पादित किया गया था, प्रेषित किया गया था या चिपकाया गया था जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था, हस्ताक्षर नहीं किया गया था, मुहर नहीं लगाई गई थी, निष्पादित नहीं किया गया था या चिपकाया गया था; या

दूसरा-जो वैध प्राधिकरण के बिना, बेईमानी या धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उसके किसी भी भौतिक हिस्से में, खुद या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ बनाए जाने, निष्पादित या चिपकाए जाने के बाद, बदल देता है, चाहे वह व्यक्ति इस तरह के परिवर्तन के समय जीवित हो या मृत; या

तीसरा-जो बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर करने, मुहर लगाने, निष्पादित करने या बदलने का कारण बनता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने का कारण

बनता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति चित विकृति या नशा के कारण नहीं कर सकता है, या यह कि उस पर किए गए धोखे के कारण, वह दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जानता है।

दृष्टांत

23. माननीय उच्चतम न्यायालय के पास अवसर था कि मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, [(2009) 8 एस. सी. सी.751] में समान तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें।

जो बिहार के मधुबनी जिले से आया था। इस मामले में भी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त द्वारा भूमि को बिना किसी स्वामित्व के बेच दिया गया था। सह-अभियुक्त बिक्री-विलेख के संबंध में गवाह, लेखक और विक्रेता थे। विद्वान दंडाधिकारी ने भा.दं.सं. की धारा 467, 471, 420 और कुछ अन्य धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के विश्लेषण के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित निर्णय दिया:

“17. जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी संपत्ति का दावा करते हुए दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है जो उसकी नहीं है, तो वह यह दावा नहीं कर रहा है कि वह कोई और है और न ही वह यह दावा कर रहा है कि वह किसी और द्वारा अधिकृत है। इसलिए, ऐसे दस्तावेज़ का निष्पादन (कुछ संपत्ति को संप्रभित करने के लिए जिसका वह मालिक नहीं है) संहिता की धारा 464 के तहत परिभाषित एक झूठे दस्तावेज़ का निष्पादन नहीं है। यदि जो निष्पादित किया जाता है वह झूठा दस्तावेज़ नहीं है, तो कोई जालसाजी नहीं है। यदि कोई जालसाजी नहीं है, तो न तो धारा 467 और न ही संहिता की धारा 471 आकर्षित होती है।

(जोर दिया गया)

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,

[(2021) 14 एस. सी. सी. 626] मामले में भी निम्नलिखित निर्णय दिया:

“24. एक कपटपूर्ण, मनगढ़ंत या जाली विलेख का अर्थ एक ऐसा विलेख हो सकता है जिसे वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया था, बल्कि एक ऐसा विलेख जो दृश्यमान निष्पादकों के जाली हस्ताक्षर करके कपटपूर्ण तरिके से बनाया गया था। यह कहना एक बात है कि बेला रानी ने धोखाधड़ी/कपटपूर्ण तरिके से संपत्ति की बिक्री को अधिकृत करने के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया, यह जानते हुए कि उसके पास संपत्ति संप्रेषित करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कहना एक और बात है कि पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप में एक जाली, कपटपूर्ण, मनगढ़ंत या निर्मित था, जिसका अर्थ है कि इसे बेला रानी द्वारा कभी निष्पादित नहीं किया गया था। उसके हस्ताक्षर जाली थे। यह समझना असंभव है कि जांच अधिकारी प्रथम दृष्टया कैसे संतुष्ट हो सकते थे कि विलेख जाली या मनगढ़ंत था या कपटपूर्ण थी, यहां तक कि प्रत्यक्ष/दृश्यमान निष्पादक बेला रानी की जांच किए बिना, जिसे गवाह के रूप में भी उद्धृत नहीं किया गया है।

25. प्रस्तुत मामले में भी प्रश्नगत बिक्री-विलेख को निष्पादित करते समय किसी भी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण का आरोप नहीं है। किसी ने भी शिकायतकर्ता या किसी और के जाली हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अभियुक्त, अरुण उरांव ने याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रश्नगत-भूमि के संबंध में बिक्री-विलेख को वास्तविक पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर निष्पादित किया है। इसलिए, प्रश्नगत बिक्री-विलेख वास्तविक है और जाली दस्तावेज नहीं है। क्या यह हस्तांतरिती को स्वामित्विक अधिकार देता है, यह एक कानूनी प्रश्न है जिसका निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाना है। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 और 471 अभियुक्त-याचिकाकर्ता के खिलाफ आकर्षित नहीं होती हैं।

26. जहां तक प्रस्तुत मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के लागू होने का सवाल है, मैं पाता हूं कि इस धारा के तत्व इस प्रकार हैं जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद इब्राहिम मामला (ऊपर)** मामले में समझाया है।

“18.....

(क) मिथ्या या भ्रामक अभ्यावेदन करके या बेईमानी से छिपाकर या किसी अन्य कार्य या लोप द्वारा किसी व्यक्ति को धोखा देना;

(ख) उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को सौंपनें या किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रतिधारण के लिए सहमति देने के लिए कपटपूर्ण या बेईमानी से प्रलोभन देना या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करना जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि उसे धोखा नहीं दिया जाता; और

(ग) ऐसा कार्य या लोप जिससे उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या क्षति या नुकसान हो या होने की संभावना हो ।

19. धारा 420 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, न केवल धोखाधड़ी होनी चाहिए, बल्कि इस तरह की धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, आरोपी को ठगे गए/धोखा दिए गए व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित करना चाहिए था

(क) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या

(ख) किसी मूल्यवान प्रतिभूति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बनाना, बदलना या नष्ट करने के लिए (या कुछ भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है)।

20. जब किसी बिक्री विलेख को किसी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करते हुए निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे बिक्री विलेख के तहत खरीदार/क्रेता के लिए यह आरोप लगाना संभव हो सकता है कि विक्रेता ने स्वामित्व का मिथ्या अभ्यावेदन करके उसे धोखा दिया

है और धोखाधड़ी से उसे बिक्री प्रतिफल से अलग होने के लिए प्रेरित किया है।लेकिन इस मामले में शिकायत खरीदार/क्रेता द्वारा नहीं की जाती है।दूसरी ओर, खरीदार को सह-अभियुक्त बनाया जाता है।

21. यह शिकायतकर्ता का मामला नहीं है कि किसी भी अभियुक्त ने या तो मिथ्या या भ्रामक अभ्यावेदन देकर या किसी अन्य कार्रवाई या लोप से उसे धोखा देने की कोशिश की, न ही यह उसका मामला है कि उन्होंने उसे किसी भी संपत्ति को देने या किसी व्यक्ति द्वारा उसके प्रतिधारण के लिए सहमति देने या जानबूझकर उसे कुछ भी करने या न करने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी भी कपटपूर्वक या बेईमान प्रलोभन की पेशकश की, जो वह ऐसा करने के लिए नहीं करता या छोड़ देता यदि ऐसा धोखा नहीं दिया गया होता। न ही शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि पहले अपीलार्थी ने बिक्री विलेखों को निष्पादित करते समय शिकायतकर्ता होने का नाटक किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम अभियुक्त ने दूसरे अभियुक्त के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के कार्य द्वारा या दूसरे अभियुक्त ने खरीदार होने के कारण, या तीसरे, चौथे और पांचवें अभियुक्त ने विक्रय विलेख के संबंध में गवाह, लिपिक और टिकट विक्रेता होने के कारण, शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से धोखा दिया।

(जोर दिया गया)

27. इस प्रकार, अभियुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत कपटपूर्ण या बेईमान प्रलोभन देकर धोखा दिए गए व्यक्ति को अभ्यावेदन करना अपराध बनाने के लिए अनिवार्य शर्त है।लेकिन इस मामले में, मैं पाता हूँ कि शिकायतकर्ता का ऐसा कोई आरोप नहीं है कि किसी भी अभियुक्त ने को. बनाया है। उसे किसी भी संपत्ति से अलग होने के लिए अभ्यावेदन दिया। इस प्रकार, किसी भी अभ्यावेदन के अभाव में, शिकायतकर्ता के किसी भी कपटपूर्ण या बेईमान प्रलोभन का सवाल नहीं उठता है।

28. इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने किसी भी संपत्ति को अभियुक्त व्यक्तियों को नहीं दिया है, न ही उसने बिक्री-विलेख को निष्पादित किया है। इस प्रकार, प्रश्नगत भूमि पर उसका अधिकार/स्वामित्व, यदि कोई हो, अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि उसका अधिकार/स्वामित्व खरीदार/क्रेता को नहीं दिया जा सकता है यदि हस्तांतरण विलेख/बिक्री-विलेख किसी और द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसके पास प्रश्नगत भूमि का अधिकार/स्वामित्व नहीं है। एक खरीदार/क्रेता केवल तभी स्वामित्व प्राप्त कर सकता है जब विक्रेता के पास संपत्ति का अधिकार/स्वामित्व हो। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अपने से बेहतर स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूरेका बिल्डर्स बनाम गुलाबचंद (2018) 8 एस. सी. सी. 67**, में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया

“35. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति केवल किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी मूर्त संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित हस्तांतरित कर सकता है जो उसके पास है और इसे प्रतिफल या अन्यथा के लिए हस्तांतरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के पास किसी भी मूर्त संपत्ति में जो भी हित है, वह केवल उसी हित को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है और कोई अन्य हित नहीं, जो उसके पास स्वयं मूर्त संपत्ति में नहीं है।

36. इसलिए, एक बार जब यह साबित हो जाता है कि किसी भी मूर्त संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख को, संपत्ति के विक्रेता का उस पर कोई विद्यमान अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था, तो ऐसी संपत्ति के खरीदार/क्रेता को उसके द्वारा प्रतिफल के लिए या अन्यथा खरीदी गई संपत्ति में कोई अधिकार,

स्वामित्व और हित नहीं मिलेगा। इस तरह का स्थानांतरण एक अवैध और अमान्य हस्तांतरण होगा।

(जोर दिया गया)

29. यहां जे. आई. टी. विनायक अरोलकर बनाम गोवा राज्य और अन्य(2024 की आपराधिक अपील संख्या 393) का उल्लेख करना भी उचित होगा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल कुछ चार दिन पहले 06.01.2025 पर निर्णय लिया गया है। उस मामले में, अभियुक्त द्वारा भूमि संपत्ति में अविभाजित हिस्से को बेच दिया गया था और सह-हिस्सेदार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद इब्राहिम मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित रूप से प्राथमिकी को रद्द कर दिया:

“ 12.1 इस मामले में, यह समझना असंभव है कि अपीलार्थी ने चौथे प्रतिवादी को कैसे धोखा दिया और कैसे अपीलार्थी द्वारा बिक्री विलेखों के निष्पादन के कार्य ने चौथे प्रतिवादी को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में क्षति या नुकसान पहुँचाया या होने की संभावना थी। अपीलार्थी ने चौथे प्रत्यर्थी की ओर से बिक्री विलेखों को निष्पादित करने का इरादा नहीं किया है। उन्होंने चौथे प्रतिवादी के अधिकारों को हस्तांतरित करने का इरादा नहीं किया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी ने विषय संपत्ति को हस्तांतरित करने या वितरित करने के लिए चौथे प्रतिवादी को धोखा दिया।

(जोर दिया गया)

30. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं पाया गया है।

31. यहां तक कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तत्व भी पूरे नहीं होते हैं। याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त द्वारा किसी भी अवैध कार्य को करने के लिए कोई समझौता नहीं किया गया है।

इस न्यायालय का निष्कर्ष/निष्कर्ष

32. इसलिए, मेरे विचार में, शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 467,468,471,420 और 120 बी के तहत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है। वर्तमान मामले के कथित तथ्य और परिस्थितियाँ, अधिक से अधिक, पक्षों के बीच विशुद्ध रूप से दीवानीप्रकृति का विवाद हैं, जिसका समाधान उचित दीवानी मुकदमा दायर करके दीवानी अदालत के समक्ष निहित है। इसलिए, विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रद्द और अपास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

33. तदनुसार, वर्तमान याचिका 2013 के शिकायत मामला संख्या 74 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित दिनांकित 04.01.2016 के विवादित आदेश को रद्द करते हुए स्वीकार की जाती है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

शोएब/रवि शंकर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।